

केंद्र द्वारा क्रपिटो को PMLA के अधीन लाया गया

प्रलिस के लिये:

क्रपिटो करेंसी, PMLA, ईडी, आभासी डजिटल परसिंपत्ता(VDA) ।

मेन्स के लिये:

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्रपिटो ।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटफिकेशन के ज़रिये [आभासी डजिटल परसिंपत्ता \(VDA\)](#) या [क्रपिटो करेंसी](#) को [प्रविशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट \(PMLA\)](#) के तहत लाया गया है। ज़ि

प्रमुख बिंदु

■ आवश्यकता:

- क्रपिटोकॉरेंसी से जुड़े लेन-देन अपारदर्शी बने हुए हैं और इसके बारे में जानकारी करना मुश्किल हो रहा है।
 - यह क्रपिटोकॉरेंसी व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिये क्रपिटोकॉरेंसी बाजारों की ज़िम्मेदारी को बढ़ाता है।
- वित्त के डजिटल युग में न केवल नविशकों बल्कि राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिये इसका अनुपालन आवश्यक है। इस संबंध में क्रपिटो उद्योग का महत्त्व बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया भर के नियामक और सरकारें इस तेज़ी से विकसित हो रहे बाजार पर अधिक ध्यान दे रही हैं।
- इस उपाय से जाँच एजेंसियों को क्रपिटो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

■ मानदंड:

- VDA सेवा प्रदाता/व्यवसाय अब PMLA अधिनियम के तहत 'रिपोर्टिंग संस्था' बन गए हैं और उन्हें अन्य वनियमित संस्थाओं जैसे- बैंकों, प्रतभित्त मिध्यस्थों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों आदि के समान रिपोर्टिंग मानकों एवं केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा।

■ PMLA के अंतर्गत आने वाली गतिविधियाँ:

- आभासी डजिटल संपत्ता (VDAs) और फिएट मुद्राओं (Fiat Currencies) के बीच आदान-प्रदान।
- VDAs के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान।
- VDAs का स्थानांतरण।
- VDA या VDAs पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन।
- किसी जारीकर्ता के VDA की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी एवं प्रावधान।

संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- अधिसूचना नए मानदंडों का पालन करने के लिये संस्थाओं को पर्याप्त समय प्रदान नहीं करती है। क्रपिटो उद्योग भी चिंतित है कि एक केंद्रीय नियामक की अनुपस्थिति में क्रपिटो संस्थाएँ [प्रवर्तन नदिशालय](#) (ED) जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे व्यवहार कर सकती हैं।
- 17 मिलियन उपयोगकर्ता [फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट](#) में कर प्रणाली की घोषणा के बाद से भारतीय VDA उपभोक्ता घरेलू, केंद्रीकृत VDA एक्सचेंजों से विदेशी समकक्षों में स्थानांतरित हो गए हैं।

- भारतीय क्रपिटो व्यापारियों ने स्थानीय एक्सचेंजों से अंतरराष्ट्रीय क्रपिटो प्लेटफॉर्मों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर

से अधिक की बढ़ोतरी की है।

- इससे कर राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, साथ ही लेन-देन का पता लगाने की क्षमता में कमी आएगी, जो मौजूदा नीति संरचना के दो केंद्रीय लक्ष्यों को असफल करता है।
- VDA टैक्स आर्कटिकचर के नकारात्मक प्रभाव से पूंजी के बहरिवाह में और तेज़ी आने एवं अंतरराष्ट्रीय नविशकों के नविश की संभावना कम है।

भारत में क्रिप्टो की कानूनी स्थिति:

- **केंद्रीय बजट 2022-23** में सरकार ने क्रिप्टोकॉर्सेसी हेतु टैक्स की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई नियम नहीं बनाया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा अनुशंसति पूर्व नविध को **सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले** द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में **संसद** को सूचति कया कि RBI की चिंताओं के जवाब में **किसी भी सफल वनियमन या क्रिप्टोकॉर्सेसी के नविध के लिये "अंतरराष्ट्रीय सहयोग"** आवश्यक होगा।
- अप्रैल 2022 से भारत ने **क्रिप्टोकॉर्सेसी से हुए लाभ पर 30% का आयकर लगाया है।**
 - जुलाई 2022 में क्रिप्टोकॉर्सेसी पर स्रोत पर 1% कर कटौती के नियम लागू हुए।

आगे की राह

- अगर क्रिप्टो लॉन्डरिंग के खिलाफ कानून और दशा-नरिदेश हैं, तो नविशकों को दंडति कये जाने का डर होगा। चीजों को और अधिक सुव्यवस्थति बनाने के लिये **भारत में एकसचेंजो को एक कर वर्ष के भीतर नविशकों द्वारा नशिचति राशिसे अधिक के कये गए हस्तांतरण का पता लगाना चाहिये** और कर अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिये।
- VDA टैक्स नरिमाण के प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप **अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ के लिये वभिदति दरों के साथ एक प्रगतशील कर संरचना** को अपनाना चाहिये।
 - 2022 में VDA से संबंधति एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई, जो उपयोगकर्त्ताओं को घरेलू से अंतरराष्ट्रीय समकक्षों में बदलती है, जसिने पूंजी के बहरिवाह को आगे बढ़ाया।

स्रोत: दैनिक जागरण

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/centre-brings-crypto-under-pmla>